

एक्स सी०ए०न० - 13487/26, सत्यप्रतिलिपि, परिवाद प्रकरण क्रमांक - 2637/2025,
पेशी दिनांक - 29.09.2026

न्यायालय- श्रीमान् प्रीति पालीवाल, न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी रायपुर छ०ग०

पक्षकार-अंतराल फायर्नेस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लिमि० पंजीकृत कार्यालय जी-32 हीरा आर्कड नया बस स्टैंड
पंडरी जिला-रायपुर छ०ग० अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुरेन्द्र शर्मा आ०-स्व० पुरुषोत्तम लाल शर्मा बनाम 1. M/
s. Darshil Technology pvt.ltd. No. 49/50/31/1, 3rd cross, Hommadevanahalli C.K.
Palya Main road B.G. Road Bangalore 2. Mr. Umesh Kulal M/s. Darshil Technology
Pvt.Ltd.No. 49/50/31/1, 3rd cross, Hommadevanahalli C.K. Palya Main road B.G.
Road Bangalore Other add Mr. Umesh Kulal (Proprietor) M/s. Darshil Technology
pvt.ltd.

07.09.2026

परिवादी द्वारा श्री संदीप अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित ।
अभियुक्त द्वारा श्रीमती पदमावती दुबे अधिवक्ता उपस्थित
प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 143(क) एन.आई.ए. पर
आदेश हेतु नियत है ।

परिवादी ने उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
अभियुक्तगण के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा
138 के अंतर्गत वर्तमान शिकायत दर्ज की है जो इस न्यायालय के
समक्ष आपराधिक शिकायत प्रकरण संख्या 2637/2025 के रूप में
पंजीकृत है । अभियुक्त क्रमांक 01 ने शिकायतकर्ता के प्रति अपनी
कानूनी रूप से प्रवर्तनीय देनदारी के निर्वहन में शिकायतकर्ता के पक्ष
में अपने बैंक खाते पर आहरित एक चेक संख्या 047497 दिनांक
11.10.2024 को 2,00,000/-रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की
राशि के लिये जारी किया था । उक्त चेक शिकायतकर्ता द्वारा अपने
बैंकर के समक्ष उसकी वैधता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जाने
पर "अपर्याप्त निधि" की टिप्पणी के साथ अनादरित होकर बिना
भुगतान के वापस आ गया । इसके पश्चात शिकायतकर्ता ने निर्धारित

N-f
N-f
for compliance
N/B
(नाना अग्रवाल)





Order Sheet [Contd.]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अवधि के भीतर अभियुक्तगण को वैधानिक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें चेक की राशि का भुगतान करने के लिये कहा गया लेकिन नोटिस की तामील के बावजूद अभियुक्तगण ने भुगतान करने में विफल और अपेक्षा की जिससे शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य होना पडा। न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है और उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप तथ्य किये गये है और अभियुक्त द्वारा बचाव का विकल्प चुना है और इस प्रकरण में बचाव करना चाहता है। शिकायतकर्ता ने शिकायत के साथ शपथ पत्र अपना साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और यह इस न्यायालय के न्यायिक रिकार्ड का हिस्सा है। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 143 ए के अंतर्गत यह प्रावधान प्रतिरक्षा साक्ष्य के पूर्व है कि न्यायालय के चेक के अभियुक्त को शिकायतकर्ता को अंतरिम प्रतिकर जो चेक राशि के 20 प्रतिशत हो का भुगतान करने का निर्देश देने के लिय सशक्त है। वर्तमान मामले में चेक की राशि 2,00,000/-रुपये है और शिकायतकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 143 ए के अनुसार इसके 20 प्रतिशत की दर से अंतरिम प्रतिकर अर्थात 40,000/-रुपये (चालीस हजार रुपये मात्र) की मांग करता है। शिकायतकर्ता ने रिकार्ड पर मौजूद अनादरित चेक वापसी मेमो और कानूनी नोटिस के आधार पर अभियुक्त की देनदारी का एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उपधारणाएं शिकायतकर्ता के पक्ष में है। इसलिए यह न्याय के हत में है कि अंतरिम प्रतिकर प्रदान किया जावे। उपरोक्त वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 143 ए के तहत वर्तमान आवेदन को स्वीकार कर अभियुक्तगण को चेक राशि 2,00,000/-रु. का 20 प्रतिशत अर्थात 40,000/- रुपये (चालीस हजार रुपये मात्र) का अंतरिम प्रतिकर शिकायतकर्ता को विहित समय के भीतर भुगतान करने तथा आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है। अभियुक्त का जवाब इसप्रकार है कि परिवादी द्वारा धारा 143 ए के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में लगाये गये आरोपों को अभियुक्त स्वीकार नहीं करते है। परिवादी ने अपने आवेदन में प्रकरण के	

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	तथ्यों को एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत किया है तथा वास्तविक विवाद एवं अभियुक्त के बचाव को न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादी के द्वारा कथित चेक क्रमांक 047497 दिनांक 11.10.2024 राशि 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये) को लेकर जो कथन किये गए हैं उसके संबंध में अभियुक्त का विशिष्ट बचाव है कि उक्त चेक के संबंध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियां विवादित हैं केवल चेक प्रस्तुत किये जाने एवं उसके अनादरित होने के आधार पर परिवादी को धारा 143 ए के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। धारा 143 ए के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर प्रदान करना न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार के अधीन है। उक्त प्रावधान का प्रयोग प्रत्येक मामले में यांत्रिक अथवा स्वतः नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, अभियुक्त के बचाव, उपलब्ध दस्तावेजों तथा परिस्थितियों का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात ही कोई आदेश पारित करना उचित होगा। वर्तमान प्रकरण में परिवादी के दावे एवं कथित देनदारी के संबंध में गंभीर विवाद एवं बचाव उपलब्ध है अतः इस स्तर पर परिवादी के पक्ष में 40,000/- (अक्षरी-चालीस हजार रुपये) का अंतरिम प्रतिकर निर्धारित किया जाना अभियुक्त के वैधानिक बचाव एवं निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। परिवादी द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है कि कथित चेक किस वैध एवं वर्तमान देनदारी के निर्वहन हेतु जारी किया गया था तथा राशि 2,00,000/- (अक्षरी-दो लाख रुपये) की कथित देनदारी किस आधार पर उत्पन्न हुई। उक्त प्रश्न परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं धारा 143 ए का आवेदन मुख्यतः उन्हीं आरोपों पर आधारित है जिनका अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विचारण में विधिवत प्रतिपादित किया जाना है। अतः इस स्तर पर परिवादी के कथन को अंतिम रूप से सत्य मानकर अंतरिम प्रतिकर प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष अपना संपूर्ण बचाव प्रस्तुत करने तथा परिवादी के दावे एवं दस्तावेजों को विधि अनुसार चुनौती देने का अधिकार रखते हैं। धारा 143 ए का उद्देश्य अभियुक्त के वैधानिक बचाव को निष्प्रभावी करना नहीं है। परिवादी द्वारा 2,00,000/- की राशि के 20 प्रतिशत अर्थात् 40,000/- रु. अंतरिम प्रतिकर के रूप में मांगे	





Order Sheet [Contd.]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	गये हैं किंतु वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उक्त राशि प्रदान करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार परिवादी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है । परिवादी के आवेदन में वर्णित समस्त आरोपों एवं तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जावे जो तथ्य विशेष रूप से स्वीकार नहीं किये गये हैं वे सभी अस्वीकृत एवं विवादित हैं । परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 143 एक के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरिम प्रतिकर संबंधी आवेदन को निरस्त कर एवं उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है । आवेदन, जवाब पर विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से परिलक्षित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2,00,000/- रुपये राशि का चेक जारी किया जाना, उसका अनादरण तथा विधिक मांग सूचना के उपरांत भी प्रश्रुत चेक राशि का भुगतान न किया जाना कथित है । अभियुक्तगण द्वारा अपने जवाब में परिवादी का आवेदन का विरोध करते हुए अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत किया गया है । परक्राम्य लिखत अधिनियम 143(ए) के अनुसार अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने की शक्ति विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राकेश रंजन श्रीवास्तव विरुद्ध स्टेट ऑफ झारखंड व अन्य 2024 INSC 205 में प्रतिपादित किया गया है कि उक्त शक्ति का प्रयोग परिवादी के प्रथम दृष्टया मामले, अभियुक्त के प्रतिरक्षण तथा प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना है । प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध चेक व अनादरण संबंधी दस्तावेज से परिवादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण परिलक्षित होता है । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रतिरक्षण पर विचार पश्चात यह परिलक्षित है कि बचाव पक्ष के तथ्यों की सत्यता एवं प्रामाणिकता का अंतिम निराकरण साक्ष्य मूल्यांकन के पश्चात ही संभव है । वर्तमान स्तर पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं है, जिसके कारण धारा 143 ए के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर प्रदान किया जाना अनुचित प्रतीत होता है । चेक राशि 2,00,000/- रु. है । धारा 143 ए(2) के अनुसार 20 प्रतिशत तक अंतरिम प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है । प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं	

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए चेक की राशि का 20 प्रतिशत अर्थात् 40,000/-रु. अंतरिम प्रतिकर के रूप में निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा 143(क) पराक्राम्य लिखत अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह 40,000/-रु.(अक्षरी-चालीस हजार रुपये) की राशि आदेश दिनांक से 60 दिवस के भीतर अंतरिम प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 143 ए के निराकरण हेतु की गई उपरोक्त विवेचना प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है तथा इसका प्रभाव प्रकरण के अंतिम गुणदोष के निराकरण तक नहीं होगा। प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगमी तिथि पर परिवादी साक्ष्य हेतु तत्पर रहे। बचाव पक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह भी प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित रहे। प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 21.09.2026 (प्रीति पालीवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, छत्तीसगढ़ परिवादी साक्ष्य हेतु - <u>सत्य प्रतिलिपि</u> बचाव पक्ष साक्ष्य हेतु - <u>सत्य प्रतिलिपि</u> प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु - <u>सत्य प्रतिलिपि</u> (सत्य प्रतिलिपि) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर (छ.ग.)	N.F. 21/9/26 20 N.F. 29/9/26 (अंतरिम प्रतिकर) N.F. 29/09/26 20 N.F. 29/09/26 20

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)





पञ्चशेखर कुं

09/09/26	1. Application Received on
11/09/26	2. Application form appeared on
23/09/26	3. Application applied on
09/09/26	4. Application sent to court for further
	or
	Record
	5. Application sent to court for
	for further
22/09/26	6. Application sent to court for further
	or
	7. Application sent to court for further
	8. No. of copies sent for 1 compl
23/09/26	9. Copy sent on
30/09/26	10. Copy delivered or sent on
	11. Court fees realised

8